

**आगामी सचेतक सम्मेलन**

973. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में भोपाल में हुए आठवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन नवंबर-सम्मेलन 1973 में रागमीर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त नवंबर सम्मेलन अभी तक आयोजित नहीं किया जा रहा ; और

(ग) नवंबर सचेतक सम्मेलन कब और कहा आयोजित करने का प्रस्ताव है ?

निर्वाण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुदामय्या) (क) से (ग) . वर्ष 1972 में भोपाल में हुए आठवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के समय जम्मू और रागमीर विधान सभल में सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा आगामी सचेतक सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित करने के लिए नियन्त्रण दिया गया था । यह नियन्त्रण राज्य सरकार की सुविधाधीन सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । यह सम्मेलन निम्न वर्ष में किया जाना चाहिए इस बारे में कोई निर्णय ही लिया गया था । इस समय देश में विद्यमान विप्लव आर्थिक मंद को ध्या में रखते हुए नव अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन को जलू विरुद्ध वर्ष के दौरान आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**Additional Wheat for Orissa**

974. SHRI CHINTAMANI PANI-GRAHI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Orissa Government had requested the Centre to release extra quantity of wheat in the months of July, August, September and October, 1974; and

(b) if so, Government's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a). Yes, Sir.

(b). The allotment of wheat which was 8,000 tonnes per month for July and August, 1974 was increased to 16,000 tonnes for September and 20,000 tonnes for October. This was further increased to 25,000 tonnes for November, 1974.

**Fertiliser Loans from Cooperatives**

975. SHRI CHINTAMANI PANI-GRAHI. Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government had advanced Rs. 400 crores to the co-operatives of different States for advancing fertiliser loans to the farmers last year;

(b) how much was advanced to co-operatives in Orissa for this purpose last year; and how much is proposed to be advanced to them during the current year; and

(c) has the Government come to know that there are fertiliser stocks worth Rupees 40 crores with the co-operatives in Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) (a) Government of India have not advanced fertiliser loans to co-operatives during 1973-74 and 1974-75. However, Government of India has sanctioned short term loans for inputs which includes fertilisers to various

States of the order of Rs. 53.9352 crores during 1973-74 and Rs 56.29 crores during 1974-75 (upto 31-10-1974).

(b) No loan to cooperatives in Orissa has been advanced by Government of India during 1973-74 and 1974-75. Government of India had sanctioned Rs. 1.50 crores and Rs. 3.31 crores to Orissa State Government as short term loans for agricultural inputs including fertilizers during 1973-74 and 1974-75 (upto 31-10-1974) respectively.

(c) Fertilizer stocks valued at Rs. 14.92 crores (approximately) were with Orissa State Cooperative Marketing Federation as on 31st August, 1974.

राज्यो में गेहूँ के थोक व्यापार की सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना

976. श्री श्रीकृष्ण प्रसवाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(i) क्या पञ्जाब सरकार ने फिजी क्षेत्र में गेहूँ के थोक व्यापार को संभालने के उद्देश्य से अपना क्षेत्र स्वतंत्र करने का निर्णय लिया है,

(ii) यदि हाँ तो उसके उद्देश्य क्या हैं ?

(iii) दूसरे राज्यों की क्या प्रतिक्रिया प्रतीकृत है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णसाहिब पी० शिन्डे) (i) और (ख) भारत सरकार की पत्र व्यवस्था से पञ्जाब सरकार ने गेहूँ के थोक व्यापार को संभालने के लिए 100 क्विंटल स्टोराज की क्षमता वाली निजीकरण के लिए गेहूँ की थोक व्यापार को संभालने के लिए प्रस्ताव किया है।

आदेश 1973 में संशोधन किया है। व्यापारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कदाचारों को रोकने के लिए यह आवश्यक समझा गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Steps to combat Soil Erosion, Flood and Water Logging

977. SHRI RAM SHEKHAR PRASAD SINGH:  
SHRI MOHAN SWARUP:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether the attention of Government has been drawn to a recent press report under the caption 'Erosion hits 15 hectares' wherein it has been stated that India will have to spend a staggering amount of Rs 30,000 crores to Rs 50,000 crores over a period of 30 years to contain the threats posed by soil erosion, floods and water logging,

(b) whether the Union Government have examined the said report; and

(c) if so, the reaction of the Union Government and the steps likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir

(c) The Government of India were seized of the problems of land and soil management even before appearance of the press report in question. With a view to tackling these problems in a coordinated and scientific manner, the Government appointed a Committee on 12-7-1974 under the Chairmanship of Member (Agriculture), Planning Com-